

कैबिनेट बैठक में सीएम ने प्रभारी मंत्रियों को दिए निर्देश, कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

माह में एक बार मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में बिताना होगी रात

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करें और वहां रात्रि विश्राम करें। यह कदम जिलों में प्रशासनिक गतिविधियों पर करीबी नजर रखने और स्थानीय जनता के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने मदरसों में अन्य धर्मों की धार्मिक शिक्षा पर प्रतिवर्ध लगाने के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी बच्चे को उसके धर्म के अलावा अन्य धर्म की शिक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ऐसे मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े विविध पक्षों पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नगरीय क्षेत्र में खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए आर्थिक अपराध अन्वेषण व्यूरो (ईओडब्ल्यू) का

विस्तार करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में 10 में से 7 संघागों में संचालित ईओडब्ल्यू कार्यालय अब शहडोल, नर्मदापुम और चंबल सभाग में भी स्थापित किए जाएंगे। इसका कैबिनेट में निर्णय लिया गया।

नर्मदा के समग्र विकास के लिए समिति गठित जीवनदायिनी नर्मदा के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के साथ समिति का गठन किया जाएगा। नर्मदा के उद्धम स्थल से लेकर गुजरात सीमा तक नगरीय निकाय और पंचायत राज संस्थाएं नर्मदा के प्रवाह की निरंतरता और सहायक नदियों, जल स्रोतों को लेकर काम करेंगी। इसमें नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, पंचायत ग्रामीण मंत्री राजस्व मंत्री और वन मंत्री समिति के सदस्य होंगे। समिति के सचिव और मुख्य सचिव और सहायक सचिव समिति की हर माह में एक बार बैठक आयोजित होगी।

भार का बंटवारा होगा। इस योजना से महिलाओं के सशक्तिकरण, विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा के लिए काम होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा।

साइबर तहसील प्रोजेक्ट का प्रदेश स्तर पर होगा।

राज्य सरकार चार नए मिशनों- युवा शक्ति मिशन,

महिला सशक्तिकरण मिशन, किसान कल्याण मिशन,

और गरीब कल्याण मिशन- की शुरुआत करने से जा रही है। इन मिशनों का उद्देश्य युवाओं, किसानों, महिलाओं, और गरीब कल्याण है।

प्रशासन अकादमी भोपाल में सामान्य प्रशासन विभाग इसके लिए एक मध्यम कार्यक्रम आयोजित करेगा। साइबर तहसील प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय स्तर पर सराहा हो रही है, अब इसका सहायक नदियों, जल स्रोतों को लेकर काम करेंगे।

मिशन नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, पंचायत ग्रामीण मंत्री राजस्व मंत्री और वन मंत्री समिति के सदस्य होंगे। समिति के सचिव और मुख्य सचिव और सहायक सचिव समिति की हर माह में एक बार बैठक आयोजित होगी।

महिला सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 364 पदों को स्वीकृति दी है।

इसमें केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में वित्तीय

लाभाग्र 1320 करोड़ रुपये से चितरंगी दाव युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इससे 32 हजार से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

मंत्री राजपूत पर लगे थे जमीन हड्डपने और अगवा कराने के आरोप

भोपाल में मिले लापता ओबीसी नेता परिजनों ने किया पहचानने से इंकार

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। आठ साल से लापता ओबीसी नेता मान सिंह पटेल भोपाल में मिलने के बाद उन्हें परिजन ने पहचानने से इंकार कर दिया है। पटेल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोजने का प्रयास किया जा रहा था। दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर ओबीसी नेता मान सिंह पटेल की खोजने के बाद खोजने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने एक व्यक्ति को छोला श्मशान घाट के पास से पकड़ा है, जिसका हुलिया मान सिंह पटेल से मिलता है, लेकिन परिजनों ने उसको पहचान करने से इनकार कर दिया है। प्राइवेट सरकार हरी नारायणचारी मिश्र ने बताया, हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति छोला श्मशान घाट के पास है, जिसका हुलिया मान सिंह पटेल से मिलता-जुलता है। इस पर हमारी टीम ने उसे पकड़कर सागर पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि, अभी परिजन पहचान से इनकार कर रहे हैं।

साल 2016 से गायब हैं मान सिंह पटेल

बता दें कि यह मामला जब तक आरोपी ने उसको ले लिया है। जब मान सिंह पटेल ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर अपनी पुश्तेनी पर अवैध कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से वह लापता हो गए थे। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर पटेल के बेटे सीताराम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें पुलिस की



निष्क्रियता पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नारायणी जाता हुए एक नई एसएआईटी (विशेष जांच दल) के गठन का आदेश दिया है। इसके बाद से पुलिस भी इस मामले में सक्रिय हो गई है।

अब डीएनए टेस्ट से होगी पहचान की पुष्टि

भोपाल से बरामद व्यक्ति का हुलिया बदला हुआ है और परिजनों ने भी उसकी पहचान करने से इनकार कर दिया है। वह छोला श्मशान घाट के पास जड़ी बूझी हो गए थे। इस मामले की शिकायत दर्ज करने के बाद से पुलिस कोर्ट के फैसले के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं मैं खुद चाहता हूं कि मामले की सही जांच हो और सच्चाई सामने आए। इस प्रकरण से मेरा कोर्ट लेना-देना नहीं है।

रहा है। इसलिए अब डीएनए टेस्ट से पहचान की जाएगी। इस टेस्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पकड़ा गया व्यक्ति वास्तव में मान सिंह पटेल है या कोई और है।

इस प्रकरण में शामिल होने से मंत्री ने किया इनकार

इन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं मैं खुद चाहता हूं कि मामले की सही जांच हो और सच्चाई सामने आए। इस प्रकरण से मेरा कोर्ट लेना-देना नहीं है।

ये बोरोजगार भी करेंगे प्रदर्शन।

पटवारी भर्ती जांच रिपोर्ट

तक ये नहीं बताया गया है कि किन्हें पदों पर भर्ती होगी?



तक ये नहीं बताया गया है कि किन्हें पदों पर भर्ती होगी?

3. ढार्लै टीपिल भर्ती की प्राप्ति के लिए जारी नहीं होने के विरोध में रिजल्ट जारी नहीं होने के विरोध में बोरोजगार सेना में उत्तरेंगी।

4. लाखों पद बैंकलॉग के खाली पड़े हुए हैं, सरकार इन पर भर्ती नहीं होती है।

5. पिछले 8 सालों से सब इंपैक्टर की भर्ती हुई है।

6. शिक्षक पात्रता की भर्ती तक मुख्य परिक्षा की तारीख नहीं आई है।

2. शिक्षक पात्रता वर्ग- 2 में अभी

अश्लील वीडियो भी आरोपी ने किए वायरल

नाबालिंग को प्रेम में फँसाकर बनाया वीडियो, फिर देह व्यापार में धकेला

सिटी चीफ भोपाल।

राजधानी में देह व्यापार का सनसनीखेज मामला

सामने आया है। युवक ने नाबालिंग को प्रेमजाल में फँसाया।

उसका अश्लील वीडियो बनाने वाले में डरेंगे।

महिलाओं के साथ देह व्यापार करने वाले हैं।

वार-बार ग्राहकों के पास जाने से नाबालिंग परेशान हुई, तो उसने विरोध किया। इस पर आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापार कर द

सम्पादकीय

लेटरल एंट्री के जरिये नियुक्ति पर यू-टर्न लेना कितना सही?

भारत सरकार जिन शीर्ष पदों पर 'विशेषज्ञों' की सीधी भर्ती करना चाहती थी, वे सामान्य आरक्षण के दायरे में नहीं थीं। संयुक्त सचिव 10 और निदेशक/ उपसचिव की 35 भर्तियां सरकार करना चाहती थी। उसका विज्ञापन भी सार्वजनिक किया गया था। यह कवायद पहली बार नहीं की जा रही थी। इस सूची में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का नाम भी है, जिन्हें 'विशेषज्ञ अर्थशास्त्री' के कारण तत्कालीन केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया था।

सरकार मिड-लेवल पर 45 विशेषज्ञों का लेटरल एट्री के जारी नियुक्त करने जा रही थी लेकिन विरोध के चलते यू-टर्न ले लिया है। प्रधानमंत्री नंदेंद्र मोदी के निर्देश पर कार्मिक मंत्रालय ने यूपीएससी को लेटरल एंट्री से भर्ती के विज्ञापन को वापस लेने को कहा है। लेटरल एंट्री से भर्ती का मुख्य विषय कांग्रेस के साथ-साथ एलजेपी जैसे एनडीए के सहयोगी भी विरोध कर रहे थे। सरकार भले ही विरोध के आगे झुक गई लेकिन लेटरल एट्री से सरकार में उच्च पदों पर डायरेक्ट भर्ती का सिलसिला तो पहले से चला आ रहा है। दरअसल आरक्षण पर फर्जी, छद्म, झूठी, अतार्किक कहनियां गढ़ी जा रही हैं। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरक्षण और उसके आधार संविधान के जरिए मोदी-विरोध की राजनीति कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में उनका यह हथियार, कमोबेश उप्र और महाराष्ट्र में, कारगर सार्वत्रिक हुआ। राजस्थान में भी भाजपा को कुछ हद तक नुकसान झेलना पड़ा। अब उपचुनावों और राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी वे इसका इस्तेमाल करना चाहती हैं। न तो संविधान को खत्म किया जा सकता है और न ही आरक्षण छीना जा सकता है, इसे देश को ब्रह्मसत्य मानना चाहिए। यदि दलित, आदिवासी और ओबीसी के किसी बच्चे को, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर, आरक्षण की सुविधा न मिले और पहली नौकरी के समय आरक्षण की अनिवार्यता लागू न की जाए, तो वह आरक्षण-विरोध है। उस पर अंदोलित भी होना चाहिए और अदालत का दरवाजा भी खटखटाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार जिन शीर्ष पदों पर 'विशेषज्ञ' की सीधी भर्ती करना चाहती थी, वे सामान्य आरक्षण के दायरे में नहीं थीं। संयुक्त सचिव 10 और निदेशक/उपसचिव की 35 भर्तियां सरकार करना चाहती थी। उसका विज्ञापन भी सार्वजनिक किया गया था। यह कवायद पहली बार नहीं की जा रही थी। इस सूची में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का नाम भी है, जिन्हें 'विशेषज्ञ अर्थसास्त्री' के कारण तत्कालीन केंद्र सरकार ने भारतीय रिजिव बैंक का गवर्नर बनाया था। फिर योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। 1991 में जब वे केंद्रीय वित्त मंत्री बने, तो वित्त सचिव के पद पर उन्होंने मोटेंक सिंह आहलूवालिया को मांगा था। मोटेंक आईएएस नहीं थे, फिर भी देश के वित्त सचिव बनाए गए। बाद में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार में उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। इसी सूची में रघुराम राजन, विमल जालान, नंदन नीलेकण, सैम प्रितोदा, एनटीपीसी के चेयरमैन रहे पी. कपूर आदि सैकड़ों नाम दर्ज हैं, जिन्हें सरकार ने सीधे ही नौकरशाही के वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया था। ऐसी नौकरियां 1968 से दी जा रही हैं और अधिकतर कांग्रेस सरकारों के दौरान ही दी गई हैं। तब संविधान को खत्म करने और आरक्षण को छीनने के मुद्दे नहीं उठाए गए। अब भी सीधी भर्ती वाले 57 शीर्ष अधिकारी भारत सरकार में कार्यरत हैं। इन भर्तियों से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आदि के युवा दावेदार कहीं भी प्रभावित नहीं होंगे। यह मुद्दा राहुल गांधी बार-बार उठा रहे हैं। भारत सरकार में जो अधिकारी आज सचिव के पद पर हैं, वे 1990 के दशक में आईएएस बने होंगे। आरक्षण तब लागू हुआ होगा, नीतीजतन 3-4 सचिव आज अनुसूचित जाति और जनजाति के भी हैं। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकते। संघ लोक सेवा आयोग की अपनी स्वायत्तता है। लोकतंत्र में जनादेश ही अधिकार देता है। जनादेश से जिसकी सत्ता बनी है और प्रधानमंत्री, कैबिनेट आदि तय हुए हैं, तो संविधान उन्हें कुछ विशेषधाकर भी देता है। पहले तो प्रधानमंत्री ही तमाम संवेधानिक पदों पर नियुक्त करते थे। अब कमोबेश नेता प्रतिपक्ष भी चयन समिति के सदस्य हैं। लिहाजा सीधी भर्तियां भी सरकार कर सकती हैं। इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। यदि विपक्ष को कुछ गलत लगता है, तो वह सर्वोच्च अदालत में चुनौती दे सकता है।

तालिबान कुशासन के तान साल, अफगान लोगों के लिए एक दुःखज की तरह

तालिबान के तरकीबीय विदेशीय सम्बन्धों पर ज़ाहिर है। अपेक्षित तालिबान को लौटे तीन साल हो गए हैं, लेकिन इस दौरान वे कई मोर्चों पर बुरी तरफ विफल साबित हुए हैं। तालिबानी शासन महिलाओं के दमन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बिगड़ते संबंधों और अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए निर्थक संघर्ष के लिए पहचाना जाता रहा है। यही नहीं, तालिबानी शासन अफगान लोगों के लिए एक दुःख्यन की तरह है।

काबुल में तालिबानी शासन को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसने उसके गवर्नेंस मॉडल की सीमाओं को उजागर कर दिया है। इन मुद्दों को सुलझाने की उसकी क्षमता ही अफगानिस्तान की भावी स्थिरता और सत्ता में तालिबान की दीर्घजीविता को निर्धारित करेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग होना, अर्थिक संकट, सुरक्षा जोखिम और आंतरिक विभाजन उसके लिए महत्वपूर्ण बाधाएँ हैं, जिनसे आने वाले वर्षों में तालिबान को निपटना होगा। अगस्त, 2021 में काबुल पर कब्जा करने के बाद विभिन्न चुनौतियों ने उनके शासन और राजनीतिक वैधता की परीक्षा ली है। सत्ता में तीन साल रहने के बाद भी तालिबान के सामने कई प्रमुख मुद्दे बरकरार हैं।

तालिबान सरकार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, जिससे औपचारिक राजनयिक संबंध बनाने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों तक पहुंचने में उसे मुश्किल हो रही है। अफगानिस्तान विदेशी सहायता पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद से काफी कम हो गई है।

प्रतिवेदन, अतिकरणात्मक द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा प्रभावित किया है। महिला अधिकारों पर तालिबान की प्रतिबंधात्मक नीतियों, खासकर एक निश्चित उम्र के बाद लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध, की व्यापक निंदा हुई है, जिसने शासन को वैश्विक समुदाय से अलग-थलग कर दिया है। इससे घरेलू अशांति और असंतोष भी बढ़ा है। तालिबान द्वारा सख्त शरिया कानून लागू करने से मानवाधिकारों के हनन की चिंताएँ बढ़ गई हैं, जिसमें सार्वजनिक रूप से फॉसी देना और अंग-भंग करना शामिल है। इन प्रथाओं की वैश्विक स्तर पर आलोचना की गई है और इससे अफगान आबादी में डर और आक्रोश पैदा हुआ है। अफगान अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है, मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। बैंकिंग प्रणाली ढहने के कागार पर है और देश में नकदी की भारी कमी है। व्यापक बेरोजगारी और गरीबी ने मानवीय संकट को जन्म दिया है। कई अफगान लोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं और खाद्य असुरक्षा व्याप्त है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसआईएस-के) लगातार खतरा बना हुआ है, जो पूरे मुल्क में घातक हमले कर रहा है। इन हमलों से तालिबान की सुरक्षा क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। तालिबान के भीतर भी मतभेद हैं, जिसमें अलग-अलग गुट सत्ता के लिए होड़ कर रहे हैं। ये विभाजन अंदरूनी कलह को जन्म दे सकते हैं और उनके नियंत्रण को अस्थिर कर सकते हैं।

समय की सबसे बड़ी मांग अक्षय ऊर्जा

अक्षय ऊर्जा वह ऊर्जा है, जो असीमित और प्रदूषणराहित है या जिसका नवीकरण होता रहता है। ऊर्जा के ऐसे प्राकृतिक स्रोत, जिनका क्षय नहीं होता अक्षय ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं। अक्षय ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों में सूर्य, जल, पवन, ज्वारभाटा, भूताप इत्यादि प्रमुख हैं। उदाहरण के रूप में सौर ऊर्जा को ही लें। सूर्य सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिसकी रोशनी स्वतन्त्र ही पृथ्वी पर पहुंचती रहती है।

पूरी दुनिया में पारंपरिक ऊर्जा के मुकाबले अक्षय ऊर्जा की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। दरअसल वर्तमान में पूरी दुनिया पर्यावरण संबंधी गंभीर चुनौतियों से जूँझ रही है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत इस समस्या को और ज्यादातः विकराल बनाने में सहभागी बन रहे हैं जबकि अक्षय ऊर्जा एवं संरक्षित ऊर्जाएँ से विपरीत रूप से जुँझ रही हैं।



अक्षय ऊर्जा के महत्वपूर्ण क्षमता का उपयोग किया जालगा है। दरअसल आज स्वच्छ वातावरण के लिए कोयला अधारित थर्मल पावर प्लाटर्नों के बजाय क्लीन और ग्रीन एनर्जी की पूरी दुनिया को जरूरत है और इन्हें जरूरतों के रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री वन वर्लड, वन सन, वन ग्रिड की बात करते हुए इस ओर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में सौं ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है। इसमें अलावा करीब साढ़े तीन दशक पूर्व पवन ऊर्जा से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की शुरू की गई पहल के बाद देश की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी काफी बढ़ चुकी है चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत अब पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भी चौथे स्थान पर है। फिलहाल जिस प्रकार देश में शुद्ध, सुरक्षित और भरोसेमंद ऊर्जा का और तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उससे लगता है विं अगले कुछ दशकों में देश की कोयला, गैस इत्यादि प्रदूषण पैदा करने वाले स्रोतों से ऊर्जा पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक भारत के अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 500 गीगावाट तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक देश के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करने, दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था का कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करने तथा वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है।

हाल ही में मूडीज रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है विं भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना है और भारत को 2030 तक इस अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए 385 बिलियन डॉलर विनिवेश करना होगा। मूडीज के अनुसार भारत हालांकि 2022 तक 175 गीगावाट के अपने लक्ष्य से चूक गया २५ लेकिन 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत की गैर जीवाशम ईंधन क्षमता को प्रतिवर्ष 50 गीगावाट बढ़ाने की योजना है और मूडीज के अनुमान के मुताबिक 44 गीगावाट की वार्षिक क्षमता वृद्धि भवति लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। मूडीज का कहना कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य का हासिल करने के लिए भारत को आगामी 6-7 वर्षों में 190-215 बिलियन डॉलर तथा ट्रांसमिशन और वितरण पर 150-170 बिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। मूडीज के मुताबिक भारत के मजबूत नीतिगत समर्थन ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपनी बिजली उत्पादन क्षमता में अक्षय

ऊर्जा का हस्सदारों का कराब 43 प्रतिशत तक बढ़ा। दिये हैं, साथ ही निजी क्षेत्र के निवेश को भी आकर्षित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा में लगातार वृद्धि भी देखी जा रही है लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयला अगले 10 वर्षों तक बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मूडीज का कहना है कि उसे उम्मीद है कि भारत अगले पांच से छह वर्षों में कोयला आधारित क्षमता में प्रतिवर्ष 40-50 गीगावाट जोड़ेगा, जिससे बिजली की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी, जो इस अवधि में 5-6 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ने की संभावना है। बहरहाल, आने वाले वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षमता को तेजी से बढ़ाने के लिए काफी कार्य करना होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि डेंगे दशक बाद भारत में सौर ऊर्जा की मांग सात गुना तक बढ़ सकती है। आज न केवल भारत बल्कि समूची दुनिया के समक्ष बिजली जैसी ऊर्जा की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा ही ऐसा विकल्प है, जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने कारगर होगी। बता दें कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है, इस दिन का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा देना है, ऊर्जा संकट और जलवाया परिवर्तन को देखते हुए, यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इसके माध्यम से अक्षय ऊर्जा के लाभों को बढ़े रूप से बताया जाता है।

इस दिन का मुख्य उद्देश्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर पवन और जल ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है, यह ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान में मददगार साबित हो सकती है, लोगों को अक्षय ऊर्जा के फायदे और इसके इस्तेमाल के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाता है।

भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरूआत 2004 में हुई थी। इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसके महत्व को समझाना है, यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास और प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। इस दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जैसे सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रदर्शनी, इन कार्यक्रमों में अक्षय ऊर्जा के लाभ, नई तकनीकी और उपयोग के तरीके पर चर्चा की जाती है, इसके अलावा, स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

• 8 / 8

आरक्षण का वांगकरण समय की माग, सुप्राम काट का निर्णय कई मायनों में क्रांतिकारी

वर्गीकरण की बहस, जो लंबे समय से चली आ रही थी, को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से दूर कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीट ने ६१ के बहुमत के फैसले में कहा कि राज्यों को राष्ट्रपति ने सूची में अधिसूचित अनुसूचित व अनुसूचित जनजातियों को उपर्याकृत करने की अनुमति प्रदान कर दी है, ताकि उन्हें सांवेदनिक रोजगार और शिक्षा में 'अधिक' अधिमान्यता प्रदान की जा सके।

वह जागीर कई नामों में प्रकाशित होता रहा। नामांकन देश में वर्चित तबकों के अंदर कई तरह के सामाजिक समृद्धाय जैसे, कामगार, हुनरमंद, कारिगर और बागवानी आदि करने वाले वर्ग सामाजिक न्याय की नीतियों और राजनीति को दुरुस्त करने के लिए लंबे समय से मुख्य हैं, लेकिन उन समृद्धायों की समाज व राजनीति में अदृश्यता है। इसलिए देश की संसद तक उनकी आवाज नहीं आ पाती है। इससे उन आवाजों को भी बल मिलेगा और उन पर विचार किया जा सकेगा।

वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट की ईक्वी चिनैया की पांच

सदस्यायी पीठ ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत वर्गीकरण पर रोक लगा दी थी, जबकि इसकी निर्णय में मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'अनुच्छेद 341(2) एक एकीकृत समरूप वर्ग नहीं बनाता है। ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि अनुसूचित जातियां सामाजिक रूप से विषम वर्ग हैं। इस प्रकार, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य अनुसूचित जातियों को और वर्गीकृत कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने उपवर्गीकरण का विरोध करने वाले अनुसूचित समुदायों के विषय पर कहा कि उनका 'रवैया टेन के सामान्य डिब्बे में बैठे व्यक्ति जैसा है। सबसे पहले, डिब्बे के बाहर के लोग अंदर? जाने के लिए संघर्ष करते हैं। एक बार वे अंदर पहुंच जाते हैं, तो बाहर के लोगों को उसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आरक्षण वर्गीकरण के विरोध में कई तरह के भ्रामक तर्कों से वर्गीकरण की बहस को भटकाया जा रहा है, जबकि? हमें फैसले को इस तरह से भी देखने की ज़रूरत है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जाति पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर स्थित सबसे कम सुविधा प्राप्त समुदायों की चिंताओं को सामने लाकर न्याय की खोज को और गहरा कर दिया है। विरोधी? रुख? उनके ही वर्ग के अतिवर्चित वर्गों में उनके लिए अविश्वसनीयता पैदा कर रहा



क इससे उनका असावधानक व्यवस्था के खिलाफ़ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी, जिसके उनके साथ लोग भी खड़े मिलेंगे, जो अब तक उनकी मुहिम में साथ खड़े नहीं दिखाई देते थे, उसका प्रमुख कारण था कि वे मुख्य व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं बन पाए थे। अलग-अलग राज्यों में अनुसूचित जाति की जातियाँ सामाजिक-राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय हैं। जैसे महाराष्ट्र में तीन दर्जन से अधिक जातियाँ शामिल हैं, लेकिन महार और मातंग सबसे प्रमुख हैं। इनकी साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से ऊच्च है। वर्धी अनुसूचित जनजातियाँ में गोंड और भील, दो सबसे बड़ी जनजातियाँ हैं, जबविं राजस्थान की राज्य सूची में कुल 59 अनुसूचित जातियाँ शामिल हैं, लेकिन मेघवाल सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है, जिसकी सामाजिक-राजनीतिक स्थिति अन्य के मुकाबले बेहतर है। वर्धी अनुसूचित जनजाति में भीण सबसे प्रमुख जनजाति है, दर्जनों विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है। समुदाय की देश भर में पुलिस और नौकरशाही में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जाटव, पासी और दुसाध सबसे प्रमुख

जबाबक इन्हीं राज्यों में मुसल्ह, सप्तरा, बहालता, कलाबाजार वाल्मीकि और बदवाल आदि दर्जनों जातियां बेहतर कमज़ोर स्थिति में हैं। न्यायमूर्ति बीआर गवर्नर ने कहा, 'लाभार्थी समूहों के भीतर असमानताओं की जमीनी हकीकत इतनी स्पष्ट है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक नौकरशाह है और एक शारीरिक मजदूर के बच्चे के साथ एक जैसा व्यवहार करना, भले ही दोनों अनुसूचित जाति समुदाय से हों, सांविधानिक जनादेश को पराजित करेगा। सामाजिक न्याय और आरक्षण का वर्गीकरण ऐसा मुद्दा है जिसमें लगातार संशोधन नहीं हुआ, तो यह एक नया जातिवाद गढ़ देगा। अतः वर्तमान में चली आ रही आरक्षण प्रणाली को एपिरिकल डाटा के आधार पर आरक्षण को देख से अधिक वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक उपसमूह के लिए जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी के आधार पर अलग-अलग कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के अंदर से उठ रही आवाजों को भी पहचाने जाने की जरूरत है, ताकि केंद्र स्तर पर आरक्षण का वर्गीकरण किया जा सके।

सिटी चीफ

क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया भुजलिया पर्व रुठे हुए को मनाने का महोत्सव

तालाब तथा नदी तट पर महिलाओं ने किया भुजलिया विसर्जन

लकेश पंचेश्वर। सिटी चीफ। लालबरा, नगर मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर कि दूरी पर स्थित ग्राम जाम के तालाब के तट पर महिलाओं के द्वारा 31 अगस्त को शाम 5:00 बजे भुजलिया विसर्जन किया गया जिसमें महिलाओं के द्वारा अपने अपने घरों के आंगन में भुजलिया को निकालकर पूजा अर्चना की गई तप्पश्चात सभी महिलाएं जाम चौक पर एकत्रित होकर ढोल शहनाई द्वारा संगीत मय वातावरण में भुजलिया को लेकर कताबद्ध रूप से तालाब की ओर प्रथमान किया तालाब के तट पर भुजलिया रखकर भुजलिया की परिक्रमा कर पूजन अर्चन किया गया एवं भुजलिया का विसर्जन किया गया इस अवसर पर ग्रामीण जनप्रतिनिधि महिला युवक युवतियां एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे यही मुख्यालय सहित जाम, नेवरगांव (ला.), बांदरी,



बहेगाव, मोहावा (जाम), छिलड़ी, खेरगाव, सहित अन्य ग्रामों में बाजे गाजे के साथ टाका तालाब में भुजलिया युवतियां सज धज कर भुजलिया को टोकरी लेकर तालाब, नदी, नदी तालौया, में पानी में ठंडा कर सर्वप्रथम भगवान को अर्पित कर रुठे हुए को मनाने का महोत्सव है। भुजली पर्व पर लोगों में खासी खुशी उत्साह देखी जाती है।

बड़ोदिया महाविद्यालय में मनाया अक्षय ऊर्जा दिवस

भगवान दास बैरागी। सिटी चीफ। शार्जापुर, शासकीय महाविद्यालय, माहौल ईश्वर दास वैष्णव। बड़ोदिया में गठित भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आज को अक्षय ऊर्जा दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्यार्थियों को अवगत करवाना, ऊर्जा के संरक्षण व सुदृपयोग के प्रति उन्हें जागरूक करना एवं भारतीय ज्ञान परंपरा में अक्षय ऊर्जा के ज्ञान चिंतन से अवगत करवाना था। कार्यक्रम का सुधाराम्भ मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में आमंत्रित मध्य प्रदेश शासन के रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, आगर मालवा के अशोक कंस्ट्रक्टर्स कंपनी के सीनियर आर्फिसर श्री गजू दास एवं आफिसर हेड, श्री गोपाल सोनार तथा प्राचार्य डॉ. एस. के. तिवारी के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ञवलन एवं माल्यार्पण द्वारा किया गया। इसके पश्चात ऊर्जा स्रोतों के प्रति एक सम्मान का भाव रखने को बात कही गयी। मुख्य वक्ता श्री राजदूस द्वारा दैवीय भाव रखते हुए।



सूर्यवंशी एवं अभिलाषा पाटीदार द्वारा विस्तार से अक्षय ऊर्जा के मूल स्रोत सूर्य देव की सुन्ति प्रस्तुत की गयी। प्राचीन द्वारा दोनों अतिथियों को पुष्पहर से स्वागत किया गया एवं उनके द्वारा अपने स्वागत भाषण में महाविद्यालय दिया गया। आयोजन प्रभारी एवं संचालक डॉ. केशव शर्मा ने अपने उद्घान में विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में अक्षय ऊर्जा के चिंतन संबंधी प्रमाणों, प्रकृति के शास्त्र ऊर्जा स्रोतों के प्रति भारतीय सम्मान का भाव रखने को बात कही गयी।

द्वारा विस्तार से अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की जानकारी दी गयी एवं साथ ही सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के निर्माण, बिजली उत्पादन एवं वितरण की तकनीक पर साराधित व्याख्यान दिया गया। आयोजन प्रभारी एवं संचालक डॉ. केशव शर्मा ने अपने उद्घान में विद्यार्थियों को आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा में अक्षय ऊर्जा के चिंतन संबंधी प्रमाणों, प्रकृति के शास्त्र ऊर्जा स्रोतों के प्रति भारतीय सम्मान का भाव रखते हुए।

सतना में हुआ इंडियाज बेरेट सिम्स गॉट टैलेंट रियलिटी शो

उमेश कुशवाह। सिटी चीफ। सतना, सेना इवेंट एंड मैनेजमेंट द्वारा की पुजारी गार्डन में रियलिटी शो के प्रथम चरण के ऑडिशंस किया गया, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं समाज सेविका एवं मधुरिमा फाउंडेशन की संस्थापक श्रीमती रघुवा वर्मा कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं बिरोड़ीय भूमेंद्र प्रताप सिंह जी, द्वारा की गई। प्रोग्राम को जज कर रही लोगारी यायिका मणिमाला सिंह एवं फिल्म अभिनेता चंद्रकान्त द्विवेदी, द्वारा लिए गए। कार्यक्रम में एक संस्थापक एवं स्नेही इवेंट के डायरेक्टर विष्णु मिश्रा जी



ने बताया कि यह ऑडिशन का पहला प्रथम चरण था, बिल्कुल निशुल्क लिया गया था, दूसरा मुंबई में किया जाएगा।

कटनी में उत्साह से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार



सुनील यादव। सिटी चीफ। कटनी, भाई और बहन के पात्रित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार सोमवार

को कटनी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अपार उत्साह, उमंग एवं हर्ष उल्लास के बीच मनाया गया। भद्रा समाप्त होते हुए रक्षाबंधन का त्योहार रात तक चलता रहा।

ही शुभ मुहूर्त में बहनों ने भाईयों की कलाई में रक्षा सुत रखी बांधकर जन्म जन्म तक सुख-दुख में साथ निभाने एवं जीवन भर रक्षा का वचन भाईयों से लिया। वहाँ भाईयों ने भी बहनों को उपाधि देकर होशा साथ निभाने का बादा किया। इस दौरान मुंह मीठा करने का दौर भी जारी रहा। घर के बुढ़े बुजुर्गों का पैर छुकर आशीर्वाद लिया गया। दोपहर में अधिकांश बहनों ने भाई की कलाई पर राखी सजाई और उपहार पाकर अपनों के साथ खुशियों मनाई। सुबह से शुरू हुआ रक्षाबंधन का त्योहार रात तक चलता रहा।

जयस के पूर्व अध्यक्ष विक्रम सिंह चौहान भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष नियुक्त

दिनेश निनामा प्रदेश उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र अजनार कार्यकारी अध्यक्ष एवं सारिंग बामनिया महासचिव हुए मनोनीत



अध्यक्ष, धर्मेंद्र अजनार को कार्यकारी जिला अध्यक्ष एवं सारिंग बामनिया को जिला महासचिव नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र असलकर, सैलाना विधानसभा क्षेत्र के व्याधक कमलेश्वर डोडियार, प्रदेश अध्यक्ष केसु निनामा, प्रदेश महासचिव बाल सिंह गामड़ ने नियुक्त पत्र प्राप्ति का ब्रांची टीम में सिलेक्शन हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश की वह पहले प्लॉयर है जिसका टीम इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ है।

भगत सिंह वर्मा ने कहा

पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण के लिए बड़ा आंदोलन होगा... घर-घर जाकर जन आंदोलन बनाएंगे



गौरव सिंघल। सिटी चीफ।

सहारनपुर, भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने ग्राम भाजपुर में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश बनाने के लिए बड़ा आंदोलन कराना चाहिए। जिसके लिए गंव- गंव, व घर-घर जाकर लोगों को जागाएंगे करके जन आंदोलन बनाया जाएगा। वर्मा ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ जनता की उन्नति के लिए पृथक राज्य का निर्माण जरूरी है। पृथक पश्चिम प्रदेश बनने पर सहारनपुर और मेरठ में एम्स की स्थापना होगी और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं होंगी। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों, 6 मंडल, 27 लोकसभा क्षेत्र, 137 विधानसभा क्षेत्र और 8 करोड़ जनसंख्या का राज्य देश ही नहीं

जनसंख्या 25 करोड़ है और यह एक दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है। जबकि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़ है और वहाँ पर 50 राज्य हैं। छोटे-छोटे राज्यों के निर्माण से ही देश की उन्नति संभव है। बैठक को संचालन करते हुए पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मिलिक ने कहा कि पृथक पश्चिम प्रदेश बनवाने के लिए हम किसी भी हाद तक जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ती हुई समस्याओं का एकमात्र हल पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण ही है जिसके लिए बड़े संघर्ष की शुरूआत राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में कर दी गई है। बैठक को संबोधित करते हुए पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक ने कहा कि पृथक पश्चिम प्रदेश बनने के लिए जिसका केंद्र बड़ा आंदोलन करें। बैठक की अध्यक्षता सुखबीर चौधरी, प्रदेश सचिव ऋषभदेव चौधरी, मंडल महामंत्री सरदार गुलबिंदर चौधरी, उद्धव चौधरी, अरविंद चौधरी इश्वाद मुखिया, यासीन त्यागी, हाजी सुलेमान, हाजी साजिद, डॉक्टर यशपाल त्यागी, धन प्रकाश त्यागी, नैन सिंह सैनी, मांगेराम सैनी, जोगिंद्र सिंह, रविंद्र प्रधान आदि ने भाग लिए।

श्रावण मास के अंतिम सोमवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ धर्म जागरण विभाग द्वारा क्षेत्र की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा निकाली

बाग बाग- राष्ट्रीय स्वयं संघ धर्म जागरण विभाग द्वारा ठांडा व बाग से 63 गांव के 1350 श्रद्धालु कावड़ यात्रा में शामिल हुए। हर हर महादेव व बोल बम के जयोत्थो से गूंज नगर। जिसमें हाथों कावड़ और भगवा ध्वज एवं तिरंगा लेकर लहरा रहे थे। लगातार 24 वर्षों से यह यात्रा निकलती आ रही है इस वर्ष भी 17 अगस्त को मेघनाथ घाट से नर्मदा का जल लेकर बाग के पास बड़केश्वर महादेव मंदिर जल अभियंक कर यात्रा बाग पहुंची जहाँ रात्रि में विश्राम सरस्वती शिशु मार्दिं में विया। सुबह नगर के महाकालेश्वर मंदिर का जल अभियंक कर कावड़ यात्रा निकली जहाँ यात्रा का नगर में जगह जगह हुआ स्वयंगत। संघ के धर्म जागरण मंच के विभाग संयोजक ईश्वर ब्रजवासी ने बताया कि यह कावड़ यात्रा



लगातार 24 वर्षों से निकाली जा रही है वनवासी क्षेत्रों में आगामी दिनों में आने वाले त्योहार

गणपति उत्सव, नवरात्रि उत्सव धूमधाम से मनाने की कार्योजना बनाई गई।

अलीराजपुर पुलिस ने बाग थाना क्षेत्र के 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के 04 तुफान वाहन जप्त किये

अलीराजपुर- दिनांक 03.08.2024 को फरियादी गिरीश बघेल निवासी ग्राम लक्ष्मणी ने थाना कोतवाली अलीराजपुर में रात में, उनके घर के बाहर अंगन में खड़ी तुफान गाड़ी किमती करोबन 08 लाख रुपये के कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा कर ले गयी की रिपोर्ट लेख करवाई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना कोतवाली अलीराजपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान मुख्यबिरु सुचना के आधार पर संदेहीयान -

1. मुकेश पिता केहरु बामनिया भील उम्र 25 साल निवासी ग्राम अखाड़ा बुदनला फलिया थाना बाग जिला धारा,
2. सालम पिता जेतरिया पवार भील उम्र 28 साल निवासी ग्राम चिकापोटी, मालपुरा फलिया थाना बाग जिला धारा,
3. इकबाल पिता कलसिह बघेल भील उम्र 22 साल निवासी ग्राम चिकापोटी मालपुरा फलिया थाना बाग जिला धारा को अभीरक्षा में लेकर पुछताछ करते ग्राम



लक्ष्मणी से तुफान वाहन चोरी करना कबूल किया।

उक्त आरोपियों से अन्य थाना क्षेत्र से चोरी की गयी 03 तुफान वाहन भी जस किये गये।

इस प्रकार उक्त आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 28 लाख रुपये किमत के 04

तुफान वाहन जस करने में सफलता प्राप्त हुई सराहनीय योगदान - SDOP अलीराजपुर अस्वनी कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रधारी अलीराजपुर शिवराम तरोले, उनि रविन्द्र प्रताप डांगो, प्रआर. 118 सुनिल डुडेंगे व आर. 475 गंगाराम, व आर. 465 नागरसिंह।

वध हेतु गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कारावास

नीमच- अंकित जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच के द्वारा कंटेनर में वध किये जाने हेतु गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपी नारू पिता मोहम्मद हुसैन, आयु- 40 वर्ष, निवासी-ग्राम बोतलगंज, जिला-मदरसोर (मप्र.) को धारा 4/9 मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000रु. अर्थदण्ड एवं धारा 11डी पशु कृत्राण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत 50रु. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्रीमती कीर्ति शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 28.10.2016 को दिन के 03-50 बजे मन्दसोर-नीमच फोरलेन रिस्ट्रेट ग्राम चत्पुर के समीप स्थित पुलिया की है। पुलिस थाना जीरन में पदस्थ एसआई जोरसिंह डामोर को मुख्यबिरु सूचना प्राप्त हुई कि एक कंटेनर जिसमें कि वध हेतु गौवंश ले जाये जा रहे हैं। मुख्यबिरु सूचना पर से कार्यवाही करते हुए एसआई जोरसिंह डामोर द्वारा मय फौस चत्पुर पुलिया के समीप पहुंचे, जहाँ उन्हें मुख्यबिरु द्वारा बताया हुआ कंटेनर आता हुव दिखाई दिया, जिसको रोककर कंटेनर को खोलकर देखा तो उसमें 37 जीवित अवस्था तथा 3 मृत अवस्था में गौवंश कीड़े बंद मिले थे। सभी गौवंश को कंटेनर में ढूंस-ढूंस कर बंद कर रखा था व भोजन-पानी-हवा की कोई व्यवस्था नहीं थी। कंटेनर को रोके जाने की कार्यवाही के दौरान आरोपी नारू हुसैन का साथी अकबर पिता मंजूर, आयु- 36वर्ष, निवासी-ग्राम बोतलगंज, जिला-मन्दसोर(मप्र.) मोके से फरार होने में सफल हो गया। आरोपी नारू हुसैन के पास गौवंश प्रियवर्ष के कोई व्यवस्था नहीं थी तथा उसके द्वारा पुछताछ में बतया गया कि वध हेतु गौवंश ले जाये जा रहा है। मुख्यबिरु सूचना पर से कार्यवाही करते हुए एसआई जोरसिंह डामोर द्वारा यह एक छोटी गौवंश कीड़े बंद कर रखने से बदल दिया गया। एसआई जोरसिंह डामोर द्वारा यह एक छोटी गौवंश कीड़े बंद कर रखने से बदल दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती कीर्ति शर्मा, एडीपीओं द्वारा की गई।

नई पहल बाबा देव पहाड़ी(टेमाची) पर सामूहिक रूप से रक्षाबंधन पर्व मनाया गया

बाबा देव समिति द्वारा समाज जनों को भोजन प्रसादी भी वितरित की गई



आम्बुआ- के पास एक छोटा सा गांव टेमाची और वहाँ निवास करने वाले आदिवासी भाईयों ने अपने कुल देवता की उपासना करते हुए नई पहल की। बाबा देव पहाड़ी पर भेस्य कुवरदेव स्थान पर बाबा देव समिति द्वारा सामूहिक रूप से रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। साथ ही गांव के आसपास के समाज जनों को एकत्रित कर भोजन के रूप में प्रसादी भी वितरित की गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बाबा देव समिति के अध्यक्ष मंगल सिंह कनेस, सचिव बापू, सिंह, कोषाध्यक्ष दिनेश कनेश, गाव के पुजारा श्री मदन सिंह अंजनार एवं साध्वी दीदी बुरी अंजनार तथा समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सराहनीय योगदान रहा। कोषाध्यक्ष दिनेश कनेश ने बताया कि समिति का

उद्देश्य हिंदू परंपरा को आगे बढ़ाना है। हमारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में बहुत से गरीब लोग हैं जो पैसों के अभाव की वजह से पारंपरिक रूप से समाज जन भी मौजूद रहे प्रेम भाव से त्योहार मना कर सभी ने जिससे वे संस्कृति से पिछड़े जा रहे हैं। हमारी समिति का उद्देश्य एक छत के नीचे रक्षाबंधन पर्व मनाना था जिससे बड़े छोटे का भेद न रहे। हमारे इस कार्यक्रम में सिर्फ हमारे गांव के ही नहीं आसपास के गांव के वजह से गांव के गांव के जाति भी मौजूद रहे प्रेम भाव से त्योहार मना कर सभी ने प्रसादी भी ग्रहण की। हमारा यही प्रयास रहेगा हर हिंदू त्योहार हम मिलकर इसी उत्साह के साथ मनाएं।

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने कल किया भारत बंद का ऐलान



का समर्थन नहीं किया है। सुप्रीमो कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी/एसटी अरक्षण में बंद करने के लिए कहा कि जिसका विवरण नहीं किया गया है।

सुप्रीमो कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी/एसटी अरक्षण में बंद करने के लिए कहा कि जिसका विवरण नहीं किया गया है।

सुप्रीमो कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी/एसटी अरक्षण में बंद करने के लिए कहा कि जिसका विवरण नहीं किया गया है।

सुप्रीमो कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी/एसटी अरक्षण में बंद करने के लिए कहा कि जिसका विवरण नहीं किया गया है।

सुप्रीमो कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी/एसटी अरक्षण में बंद करने के लिए कहा कि जिसका विवरण नहीं किया गया है।

सुप्रीमो कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी/एसटी अरक्षण में बंद करने के लिए कहा कि जिसका विवरण नहीं किया गया है।

सुप्रीमो कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी/एसटी अरक्षण में बंद करने के लिए कहा कि जिसका विवरण नहीं किया गया है।

सुप्रीमो कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी/एसटी अरक्षण में बंद करने के लिए कहा कि जिसका विवरण नहीं किया गया है।

सुप्रीमो कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी/एसटी अरक्षण में बंद करने के लिए कहा कि जिसका विवरण नहीं किया गया है।

सुप्रीमो कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी/एसटी अरक्षण में बंद करने के लिए कहा कि जिसका विवरण नहीं किया गया है।

सुप्रीमो कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी/एसटी अरक्षण में बंद करने के लिए कहा कि जिसका विवरण नहीं किया गया है।

सुप्रीमो कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी/एसटी अरक्षण में बंद करने के लिए कहा कि जिसका विवरण नहीं किया गया है।

सुप्रीमो कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी/एसटी अरक्षण में बंद करने के लिए कहा कि जिसका विवरण नहीं किया गया है।

सुप्रीमो कोर्ट ने राज्य स

